

## किसान आंदोलन 2.0 और MSP

### प्रलिस के लयः

[न्यूनतम समर्थन मूल्य](#), कसलन आंदोलन 2.0 और MSP, [भूमऱ अधगऱरहण अधनऱयऱम,2013](#), [वदऱयुत \(संशोधन\) वधऱयक 2020](#), डॉ. ँम. ँस. स्वामीनऱथन आयोग की रऱऱरुट ।

### मेन्स के लयः

कसलन आंदोलन 2.0 और MSP, ढरऱतीय अरुथव्यवस्था और योजनऱ, संसऱधनों कऱ संगरहण, वकऱस, वकऱस और रोजगऱर से संबंघतऱ मुददे ।

[सुरोतः इंडयऱन ँकसऱऱरेस](#)

### चरुचऱ में क्यऱों?

[न्यूनतम समर्थन मूल्य \(Minimum Support Price - MSP\)](#) के लयऱ कऱनूनी गऱरंटी की मऱंग को लेकर ढंजऱब, हरयऱणऱ और उत्तर ढरदेश के कसलन 'दलऱली चलो' वरऱशेध ढरदर्शन में दलऱली की ओर मऱरुच कर रहे हैं ।

- वर्ष 2020 में कसलनों ने, दलऱली की सीमऱओं ढर, सरकर दवऱरऱ ढररतऱ तीन [कृषऱ कऱनूनों कऱ वरऱशेध](#) कयऱ, जसऱके कऱरण वर्ष 2021 में उनुहें नरऱसुत कर दयऱ गयऱ ।
- ये कऱनून थे- [कृषऱ ँऱऱऱ वऱणजऱय ँवं वऱयऱऱर \(संवरुधन ँवं सुवधऱ\) वधऱयक, 2020](#), [मूल्य आशवऱसन ढर कसलन \(बंदोबसुती और सुरकृषऱ\) समझूतऱ और कृषऱ सेवऱ वधऱयक, 2020](#), [ऱवशऱयक वसुतु \(संशोधन\) वधऱयक, 2020](#)

### कसलनों की मुखऱ मऱंगें क्यऱ हैं?

- कसलनों के 12 सुतऱरीय ँजेंडे में मुखऱ मऱंग सऱभी फसलों के लयऱ [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) की गऱरंटी के लयऱ ँक कऱनून और डॉ. ँम.ँस. स्वामीनऱथन (मनकोमबु संबऱशवऱन स्वऱमीनऱथन) आयोग की रऱऱरुट के ँनुसऱर फसल की कीमतों कऱ नरऱधऱरण करनऱ है ।
  - स्वऱमीनऱथन आयोग की रऱऱरुट में कऱहऱ गयऱ है कऱसरकर को **MSP को उत्पादन की ढररतऱ ँसुत लऱगत से कम-से-कम 50% अधकऱ बढऱनऱ चऱहयऱ** । ँसे **C2+ 50% फूँरमूला** के रूऱ में भी जऱनऱ जऱतऱ है ।
  - ँसमें कसलनों को 50% रऱटऱरन देने के लयऱ **ढूँजी की ँनुमऱनऱतऱ लऱगत** और ढूमऱऱर करऱयऱ (जसऱसे 'सी2' कऱहऱ जऱतऱ है) शऱमलऱ है ।
    - ढूमऱ, शऱरम और ढूँजी जैसे संसऱधनों के ँऱऱयऱग की ँवसर लऱगत को धूँयऱन में रऱखने के लयऱ **अधऱरऱरोऱऱतऱ लऱगत (imputed cost)** कऱ ँऱऱयऱग कयऱ जऱतऱ है ।
    - ढूँजी की अधऱरऱरोऱऱतऱ लऱगत** ँस बूँयऱज यऱ रऱटऱरन को दरुशऱती है जो अरुजतऱ कयऱ जऱ सकतऱ थऱ यदऱ कृषऱ में नऱवऱश की गई ढूँजी को कऱहीं और नऱवऱश कयऱ जऱतऱ ।
- ँनूय मऱंगें:
  - कसलनों और मऱजदूरों की ढूरण करुऱऱ मऱफी;
  - [भूमऱ अधगऱरहण अधनऱयऱम, 2013](#) कऱ कऱरूयऱनूवयन, जसऱमें अधगऱरहण से ढहले कसलनों से लखऱतऱ सऱहमतऱ और कलेकुटर दर से चऱर गुनऱ मुऱऱवऱऱ देने कऱ ढरऱवधऱन है ।
    - संगरऱहक दर (collector rate)** वऱह नूयूनतम मूल्य है जसऱ ढर करऱसी संपतुतऱ को खरऱदते यऱ बेचते समय ढंजीकृत कयऱ जऱ सकतऱ है । **वे संपतुतऱयऱों के कम मूल्यऱंकन और कर चूरी को रोकने के लयऱ** ँक संदरुभ बढऱु के रूऱ में कऱरूय करतऱे हैं ।
  - ँकुटूबर 2021 में लखऱीमऱुर खऱरी हतूयऱकऱंड के ँऱऱरऱधऱयऱों को सऱऱऱ;
  - ढररत को [वशऱव वऱयऱऱर संगठन \(World Trade Organization - WTO\)](#) से बऱहर हो जऱनऱ चऱहयऱ और सऱभी [मुक्त वऱयऱऱर समझूतऱों \(free trade agreements - FTAs\)](#) ढर रोक लऱगऱ देनी चऱहयऱ ।
  - कसलनों और खेतऱहर मऱजदूरों के लयऱ ढेंशन ।
  - वर्ष 2020 में दलऱली वरऱशेध ढरदर्शन के दूरीऱन मरने वऱले कसलनों के लयऱ मुऱऱवऱऱ, जसऱमें ढरऱवऱर के ँक सदसूय के लयऱ नूकरी भी शऱमलऱ है ।

## सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

- नवंबर 2021 में भारत सरकार ने तीन कृषिकानूनों को रद्द करने के बाद MSP पर एक समिति बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य MSP पर चर्चा करना, [ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग](#) को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर नर्णय लेना था। इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था और इसने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है।
- कैबिनेट मंत्रियों और किसान संघ के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान सरकार ने [नेकृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समिति बनाने की पेशकश की](#)।
- यह समिति किसानों की सभी फसलों के लिये MSP की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा किया कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और नर्णय लेने के लिये समय सीमा के भीतर काम करेगी।

## MSP के कानून में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **जबरन खरीद (Forced Procurement):**
  - सरकार को **MSP पर सभी उपज खरीदने का आदेश** देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या हो सकती है।
  - यह **फसल पैटर्न को भी विकृत (distort) कर सकता है** क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में MSP वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैवविविधता और मट्टि के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
  - यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है क्योंकि MSP की पेशकश करने वाला कोई खरीददार नहीं है, तो उसके पास **मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लिये संसाधन नहीं हैं**।
- **किसानों का आपसी भेदभाव (Discrimination Among Farmers):**
  - ऐसा कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है।
  - बिना समर्थन वाली फसलें उगाने वाले किसानों को बाज़ार पहुँच और सरकारी समर्थन के मामले में **नुकसान का सामना करना पड़ सकता है**।
- **व्यापारियों का दबाव (Pressure From Traders):**
  - फसल कटाई के दौरान, कृषि उपज की कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं, **जिससे नर्णय व्यापारियों को फायदा होता है** जो इस समय खरीदारी करते हैं। इस वजह से, नर्णय व्यापारी MSP के किसी भी कानूनी आश्वासन का वर्णय करते हैं।
- **वित्तीय बोझ (financial burden):**
  - सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया **भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना** करना पड़ सकता है।
- **सामाजिक नर्णय (Societal Implications):**
  - विकृत फसल पैटर्न और अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जो **खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता** को प्रभावित कर सकते हैं।

## MSP को कानूनी रूप देने के बजाय किसानों की आय की रक्षा के लिये क्या पहल की जा सकती है?

- विशेषज्ञ **केवल MSP पर नर्णय रहने के बजाय किसानों को सीधे पैसा देने का सुझाव** देते हैं। इस तरह, किसानों को स्थिर आय मिलती है, चाहे बाज़ार कैसा भी हो।
  - इसका संबंध कुछ फसलों के लिये कीमतों की गारंटी देने के बजाय किसानों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने की बड़ी समस्या को ठीक करने से है।
- **प्रत्यक्ष आय सहायता को लागू करने में वभिन्न रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं**, जैसे कि:
  - **प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण: किसानों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय तनाव कम करने के लिये सीधे नकद भुगतान प्रदान करना।**
    - सरकार पूरे मूल्य समर्थन पैकेज और उर्वरक सब्सिडी को शामिल करके तथा राजस्व-तटस्थ तरीके से किसानों को बहुत अधिक पीएम-किसान भुगतान में **PM- किसान योजना** का **वर्णय** करने के बारे में सोच सकती है।
    - यह योजना वर्णय में किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए सीधे नकद भुगतान प्रदान करती है।
  - **बीमा योजनाएँ:**
    - ऐसी बीमा योजनाएँ शुरू करना जो फसल की वफिलता, मूल्य अस्थिरता या प्रतिकूल मौसमीय स्थिति जैसे कारकों के कारण किसानों की आय के नुकसान की भरपाई करती हैं।
    - कृषि आदानों (inputs), उपकरणों, प्रौद्योगिकी अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या वैकल्पिक आजीविका में वविधीकरण का समर्थन करने के लिये सब्सिडी या अनुदान की पेशकश करना।
  - **मूल्य-अंतरण भुगतान विकल्प: सरकार MSP और किसानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी वर्णय कर सकती है।**
    - हरियाणा और मध्य प्रदेश ने **भावांतर भरपाई योजना (मूल्य-अंतरण मुआवज़ा योजना)** नामक योजना के तहत इस विकल्प को लागू किया है।
    - मध्यप्रदेश की **'भावांतर भुगतान योजना'** के तहत किसानों को भुगतान औसत बाज़ार मूल्य और फसलों के MSP के बीच के अंतर को कवर करता है। यदि किसानों को खुले बाज़ार में MSP से नीचे अपनी उपज बेचनी पड़ी, तो उन्हें मुआवज़ा दिया गया।

## WTO और FTA से संबंधित किसानों की चिंताएँ क्या हैं?

- बाज़ार तक पहुँच:
  - किसानों को चिंता है कि FTA और WTO नियमों से सस्ते कृषिआयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं तथा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।
  - किसान इन समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के किसानों के बजाय बहुराष्ट्रीय नगियों तथा बड़े पैमाने के कृषिव्यवसायों के पक्ष में मानते हैं।
- आयात वस्तुएँ:
  - इन समझौतों से अन्य देशों से सब्सिडी वाले कृषिउत्पादों की आमद होती है, जिससे घरेलू बाज़ार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमतें कम हो सकती हैं।
  - इससे भारतीय किसानों के लिये प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
- कृषिपद्धतियों पर प्रभाव:
  - अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषिपद्धतियों पर ऐसे नियम या मानक भी लागू करते हैं जिन्हें भारतीय किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों के साथ बोज़लिया या असंगत पाते हैं।
  - इसमें कीटनाशकों के उपयोग, [आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव](#) या पर्यावरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।
- संप्रभुता और स्वायत्तता:
  - कुछ किसान WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौतों पर अंकुश लगाने को भारत की कृषिनीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं।
  - उनका तर्क है कि ऐसे समझौते लघु पैमाने के किसानों के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं।

## MSP और किसानों की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

- मौजूदा MSP बनाम कृषकों की मांगे:
  - रबी मार्केटिंग सीज़न 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ का MSP 2,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो किसानों द्वारा मांगी गई लागत यानी C2 प्लस 50% से अधिक है।
  - हालाँकि MSP A2+FL फॉर्मूला पर आधारित है जिसमें केवल किसानों द्वारा भुगतान की गई लागत शामिल है जिसके परिणामस्वरूप C2 प्लस 50% की तुलना में MSP कम है।
- CACP की अनुशंसाएँ और कार्यप्रणाली:
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा करता है जिसमें केवल भुगतान की गई लागत तथा पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।
    - यह C2 फॉर्मूले से भिन्न है जिसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि के करिये और स्थिर पूंजी पर ब्याज़ जैसे अतिरिक्त कारक शामिल हैं।
- उत्पादन लागत पर रटिर्न:
  - पंजाब में गेहूँ का उत्पादन लागत (C2) 1,503 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति क्विंटल है।
    - इसका अर्थ यह है कि किसानों को उत्पादन लागत से 772 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलाता है जो उत्पादन लागत पर 51.36% का रटिर्न दर्शाता है।
  - इसी प्रकार पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर रटिर्न 49% का था और A2+FL पर यह 152% था।

## वर्श्व भर में किसान वरिोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

- दक्षिण अमेरिका:
  - किसान नरियात के लिये प्रतिक्विल वनिमिय दर, अधरिपति उच्च कर, आर्थिक मंदी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण वरिोध कर रहे हैं जिसे फसलें प्रभावित होती हैं तथा कृषि उत्पादन कम होता है।
    - ब्राज़ील में कृषक वर्ग आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के परिणामस्वरूप होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा के वरिोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - वेनेज़ुएला में किसान सहायिकी युक्त डीज़ल की मांग कर रहे हैं।
    - कोलंबियाई धान उत्पादक अपनी फसल के लिये कीमतों में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं।
- यूरोप:
  - किसान फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत, अल्प लागत वाले आयात और [यूरोपीय संघ](#) द्वारा अधरिपति सख्त पर्यावरण नियमों का वरिोध कर रहे हैं।
    - फ्रांस में अल्प लागत वाले आयात, अपर्याप्त सहायिकी और उच्च उत्पादन लागत के वरिोध वरिोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं।
- उत्तर और मध्य अमेरिका:
  - मैक्सिकन किसान मक्के और गेहूँ की फसल के लिये दिये जाने वाले अनुचित कीमतों का वरिोध कर रहे हैं जबकि कोस्टा रिका के किसान कर्ज़ के बोझ से छुटकारा पाने के लिये अधिक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।
  - मेक्सिको के चड्डिआहुआ प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमिति जल आपूर्ति नरियात करने की योजना पर वरिोध प्रदर्शन हुआ।
- एशिया:
  - भारतीय किसान फसल की गारंटीकृत कीमतों, आय दोगुनी करने और ऋण माफी की मांग को लेकर वरिोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

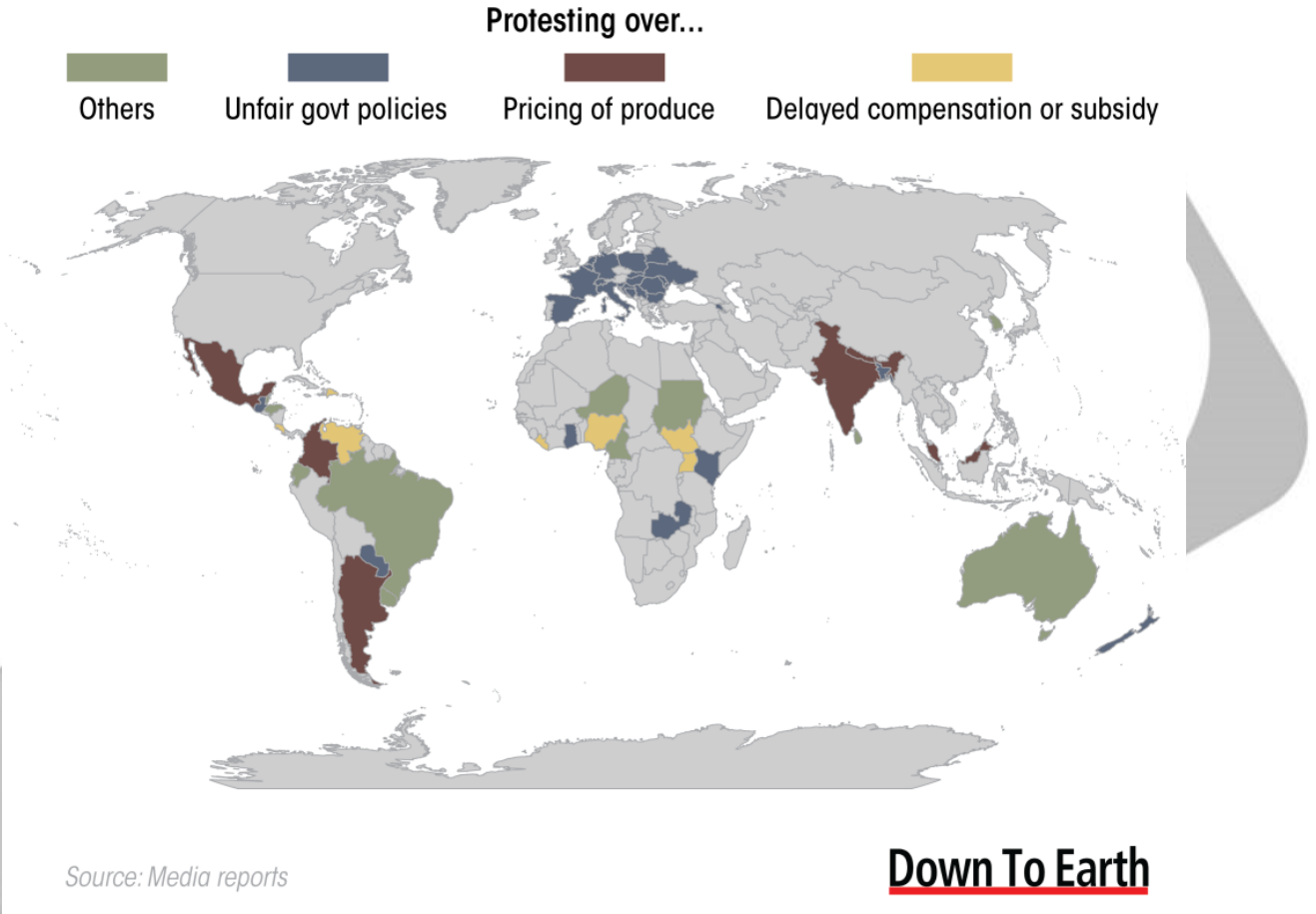
- नेपाल में आयातति भारतीय सब्जियों की अनुचित कीमतों के कारण वरीध प्रदर्शन किया जा रहा है ।
- मलेशियाई और नेपाली किसान क्रमशः चावल तथा गन्ने की कम कीमतों का वरीध कर रहे हैं ।

■ **ओशनिया:**

- न्यूज़ीलैंड के किसान खाद्य उत्पादकों को प्रभावित करने वाले सरकारी नियमों का वरीध करते हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई किसान अपनी कृषि भूमि से गुजरने वाली हाई-वोल्टेज वदियुत लाइनों का वरीध कर रहे हैं ।

## FARM PROTESTS GLOBALLY

Since 2023, at least 65 countries have reported protests organised by agricultural workers with reasons ranging from minimum support price like in India, to unfair governmental policies — like in Europe — to outright displacement or eviction of farmers as seen in Benin or Sudan in Africa



### न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

■ **परिचय:**

- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है ।
- MSP **कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP)** की सफ़ारशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है ।
  - CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है । इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया ।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)** MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है ।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और **फसल वविधीकरण** को प्रोत्साहित करना है ।

■ **MSP के तहत फसलें:**

- CACP, **22 अधिष्टित फसलों (Mandated Crops)** के लिये MSP और गन्ने के लिये **उचित तथा लाभकारी मूल्य (FRP)** की सफ़ारिश करता है ।
- अधिष्टित फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, **6 रबी फसलें** और 2 अन्य वाणज्यिक फसलें शामिल हैं ।

#### ■ उत्पादन लागत के तीन प्रकार:

- CACP प्रत्येक फसल के लिये राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
  - 'A2': इसके तहत कसिान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, संचाई आदि पर किये गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
  - A2+FL': इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधरिपति मूल्य शामिल किया जाता है।
  - 'C2': यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में कसिान की स्वामित्व वाली भूमि और स्थरि संपत्ति के करिए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफिरशि करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर वचिर किया जाता है।
  - CACP द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतफिल के लिये की जाती है।
  - जबकि 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये किक्या उनके द्वारा अनुशंसति MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।

#### ■ MSP की आवश्यकता:

- वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कघटनाओं के कारण कसिानों को वर्ष 2014 के बाद से वसतु की कीमतों में लगातार गरिवट का सामना करना पड़ा।
- वमिदरीकरण (Demonetisation) एवं 'वसतु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावति किया है।
- वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोवडि महामारी के कारण अधकिंश कसिानों के लिये परदृश्य वकिट बना हुआ है।
- डीज़ल, बजिली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है।
- यह सुनश्चित करता है किकिसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मलि, जसिसे कृषि संकट एवं नरिधनता को कम करने में मदद मलिती है। यह उन राज्यों में वशिष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।



# ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

## ❖ सिफारिश:

❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।

## ❖ 22 अधिदिष्ट फसलें :

(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)

- ❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- ❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- ❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- ❖ कच्चा कपास
- ❖ कच्चा जूट
- ❖ नारियल/गरी ( कोपरा )

**MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है**

## ❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:

- ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
- ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
- ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

## भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

### ■ सीमतिता:

- 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के वपिरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इनहीं दोनों खाद्यान्नों का वतिरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्त्वहीन ही है।
- शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्त्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि गैर-लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश कसिानों को MSP से लाभ नहीं मलित है।

### ■ अप्रभावी कार्यान्वयन:

- वर्ष 2015 की शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार कसिानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हुआ।
- जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% कसिान MSP के लाभ से वंचित रहे। इसका मुख्य कारण कसिानों के लिये अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाज़ार पहुँच है।

### ■ प्रवण फसल का प्रभुत्व:

- चावल और गेहूँ के लिये MSP पर ध्यान केंद्रित करने से इन दो प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है। इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारस्थितिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- यह बाज़ार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे कसिानों के लिये आय की संभावना सीमति हो सकती है।

### ■ बचौलियों पर नरिभरता:

- MSP-आधारित खरीद प्रणाली में प्रायः बचौलिय, कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) के अधिकारी जैसे बचौलिय शामिल होते हैं।
- विशेष रूप से छोटे कसिानों के लिये इन चैनलों तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होंगी और उनके लिये लाभ कम हो जाएगा।

### ■ सरकार पर बोझ:

- सरकार MSP समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक वृहत वतितीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का वचिलन हो जाता है जनिहें अन्य कृषि या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित किया जा सकता है।

## आगे की राह

- फसल वविधीकरण को प्रोत्साहित करने और चावल व गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिये सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन हेतु पात्र फसलों की सूची का वसितार कर सकती है। इससे कसिानों को अधिक विकल्प मल्लिगे और बाज़ार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मल्लिगा।
- MSP मुद्दे का समाधान करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कसिानों के हतियों और व्यापक आर्थिक नहितार्थ कोई शामिल किया जाना चाहिये।
  - MSP परकिलन पद्धतपर पुनः वचिार करने और MSP नरिधारित करने के लिये एक नषिपक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनश्चिति करने से कसिानों द्वारा उठाई गई कुछ चतिाओं को दूर करने में मदद मल्लि सकती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों एवं तलिनहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रापण भारत के कसिी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमति होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP कसिी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर नरिधारित किया जाता है, जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

1. भारत सरकार काले तलि नाइजर (गुइज़ोटिया एबसिनिका) के बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है।
2. काले तलि की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है।
3. भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तलि के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (2018)

प्रश्न. सहायकियों सस्यन प्रतरूप, सस्य वविधिता और कृषकों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावति करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (2017)

प्रश्न. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतस्थापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ का क्या अधदिश (मैंडेट) है और उसके नरिणय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वचिर-वमिर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ-मत का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजिये। (2014)